



मालपुरा मंडी में चने की ट्रॉली खाली कर रहा किसान अपनी उपज सात रुपए प्रति किलो की दर से बेचने को मजबूर है।

श्रीलंका में पेट्रोल का कोटा तय

कोलम्बो, 15 अप्रैल (वार्ता/शिन्हुआ)। श्रीलंका के सरकारी स्वामित्व वाली सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) ने शुक्रवार अपराह्न एक बजे से पेट्रोल पंप पर ईंधन कटौती की घोषणा की है।

सीपीसी ने कहा कि प्रत्येक मोटरसाइकिल के लिए 1,000 श्रीलंकाई रुपये (3.2 डॉलर) का ईंधन जारी होगा। तिपहिया वाहनों के लिए 1,500 रुपये और कार, वैन और जीप

के लिए 5,000 रुपये का ईंधन जारी किया जाएगा। सीपीसी के अध्यक्ष सुमित विजयिंधे ने कहा कि यह सीमा बसों, लॉरियों और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होती है। इस सप्ताह की शुरुआत में सीपीसी ने घोषणा की कि वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि और बढ़ती घरेलू मांग के कारण श्रीलंका का मासिक ईंधन आयात अप्रैल में बढ़ कर 70 करोड़ डॉलर हो गया है, जो दो महीने पहले 45 करोड़ डॉलर था। वर्ष 2021 में श्रीलंका का औसत मासिक ईंधन आयात 31.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

एक मोटरसाइकिल के लिए 1 हजार श्रीलंकाई का पेट्रोल मिलेगा।

के लिए 5,000 रुपये का ईंधन जारी किया जाएगा। सीपीसी के अध्यक्ष सुमित विजयिंधे ने कहा कि यह सीमा बसों, लॉरियों और वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होती है। इस सप्ताह की शुरुआत में सीपीसी ने घोषणा की कि वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि और बढ़ती घरेलू मांग के कारण श्रीलंका का मासिक ईंधन आयात अप्रैल में बढ़ कर 70 करोड़ डॉलर हो गया है, जो दो महीने पहले 45 करोड़ डॉलर था। वर्ष 2021 में श्रीलंका का औसत मासिक ईंधन आयात 31.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर था।

केन्द्रीय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मालिक रणरुद्रा हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं लेकिन इनके खिलाफ बहुत से केस चल रहे हैं, जिनमें सी.बी.आई. जांच वाले केस भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा है कि पी.एम.ओ. ने उस पत्रकार का इस्तीफा चाहा है तथा दरवाजा ने उसे इस्तीफे के लिये बाध्य कर दिया। लेकिन बाद में, गडकरी ने कहा कि खबर सही है तथा कैबिनेट में जो कुछ हुआ था, संबंधित पत्रकार ने उसकी बिचकल सही-सही रिपोर्टिंग की थी।

इंग्लैण्ड के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करोड़ डॉलर मिलेंगे। अगर शरणार्थियों के दावे सही पाये जाते हैं, तो उन्हें रखांडा में "रहने के कानूनों के रास्ते" उपलब्ध करा दिये जायेंगे। फ्रांस से इंग्लिश चैनल को पार करने का खतरा उठाकर ब्रिटेन आ रहे शरणार्थियों के छोटे किन्तु निरन्तर प्रवाह को रोकने के लिये, ब्रिटिश सरकार लगातार संघर्षरत रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि "इस समझौते का अंजाम देने वाला विधेयक अभी संसद में पारित होने की प्रक्रिया में है। वे इस बिन्दु पर सहमत थे कि ऐसी संभावना है कि इस योजना के सम्मुख कानूनी चुनौतियाँ आयें तथा यह योजना रातों-रात अमल में नहीं आयेगी।"

विपक्षी लेबर पार्टी की पैट कुपर ने इस योजना को "अव्यवहारिक, अनैतिक एवं लूट-खसोट वाली" योजना बताया है। उन्होंने टिवटर पर लिखा कि यह एक

चना 7 रु. प्रति किलो बेचने को मजबूर

मालपुरा, (निसं) केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, सरसों व गेहूँ की खरीद की घोषणा किये जाने के बावजूद मालपुरा में 15 दिन बाद भी क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र का कांटा शुरू नहीं किया। इस वजह से किसानों को मंडी में सात रुपये प्रति किलो के कम दामों में चना बेचने पर विवश होना पड़ रहा है, जिसके चलते 1 से 15 अप्रैल तक मालपुरा मंडी के आंकड़ों के मुताबिक किसानों को डेढ़ करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है।

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम देने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए गेहूँ, चना, सरसों

समर्थन मूल्य पर चने की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

का समर्थन मूल्य घोषित किया गया, और राजफेड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से मंडी परिसर में सरकारी कांटे लगा 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर घोषित जिनसे की खरीद शुरू की जानी थी। सरकार की घोषणा के मुताबिक किसानों ने ई-मित्र के जरिए अपनी उपज का ऑनलाइन पंजीयन भी करवाया गया। लेकिन राजफेड द्वारा किसान फसल को ऑन-पौने दामों

में मंडी में खुले में बेचने पर विवश हो रहा है, तो व्यापारी भी खुली बोली से चने की खरीद में सात से दस रुपये प्रति किलो तक दाम लगा रहे हैं और समर्थन मूल्य से कम दामों में चना खरीद कर किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।

मंडी कार्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मालपुरा मंडी में चने की 18 हजार से अधिक बोरीयों की आवक हुई है। किसान मांगीलाल, किसान, रामनिवास, प्रहलाद, हनुमान, घनश्याम, रोडू, बदाम, गीता देवी इत्यादि का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा तो कर दी लेकिन खरीद केन्द्र शुरू नहीं करने से किसानों की भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है।

मुस्लिम नेता अखिलेश से दूरी बनाने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अखिलेश के लिये मुस्लिमों की इस सोच को बदलना मुश्किल हो जायेगा कि वे मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के इतिहास में इस समुदाय की अब तक की टोस एवं सबसे बड़ी एकजुटता के लिये अपना खून-पसीना एक कर दिया था।

भगवा पार्टी के खिलाफ अपनी आक्रामक मोर्चा बंदी के बावजूद, सपा केवल 111 सीट जीतकर दूसरे नम्बर पर, किन्तु विजयी पार्टी से बहुत पीछे रही। ज्ञातव्य है कि 403 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में एन.डी.ए. ने 273 सीटें जीतकर अपने आप को सत्ता में बनाये रखा था। पिछले दिनों में, सपा मुस्लिम

समुदाय के विभिन्न खेमों की नाराजगी एवं विरोध झेलती आ रही है। जहाँ सपा के एक पदाधिकारी सलमान जावेद रईन ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया था, वहीं आजम खान के मीडिया-प्रभारी फसाहत अली शानु, सम्भल के सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क तथा बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत दरगाह के मौलवी मौलाना शहाबुद्दीन रिज्वी- इन सब ने मुस्लिम समुदाय के प्रति सपा प्रमुख के कथित उदासीन रूख को लेकर निराशा एवं अप्रसन्नता व्यक्त की है। दरगाह के मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश को मुस्लिम पसंद नहीं है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि वह सपा को छोड़कर, भाजपा में शामिल हो जाये। रिज्वी तनजीम उलेमा-ए-इस्लाम के राष्ट्रीय

महासचिव भी हैं। सुप्रसिद्ध राजनैतिक टिप्पणीकार जे.पी. शुक्ला कहते हैं, "वस्तुतः अल्पसंख्य समुदाय के अन्दर से आ रहे इस विरोध का कारण, खासतौर से विधानसभा चुनावों के बाद, मुस्लिमों में पैदा हुई कुंठा एवं निराशा-हताशा की भावना है। वस्तुतः मुस्लिमों की यह आम सोच पराजित हो गई है कि मुस्लिम एकजुटता भगवा तूफान को रोक सकती है। अब, वोट बैंक के रूप में मुस्लिमों के "अप्रासंगिक" हो जाने की भावना उनमें बढ़ती जा रही है तथा वे अपने इस निराशाजन्य भर्डास एवं आक्रोश को सपा नेतृत्व पर निकाल रहे हैं।" लेकिन शुक्ला इस बात से भी इंकार नहीं करते कि खासतौर से 2024 के

क्या मोहन भागवत का अखण्ड भारत का नारा 2024 चुनाव की तैयारी है?

इस नारे की भावात्मक अपील से सभी वाकिफ हैं, चाहे यह कल्पना कितनी भी अव्यवहारिक लगती हो, आज के परिप्रेक्ष्य में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 अप्रैल। क्या आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत, "अखण्ड भारत" का हौआ खड़ा करके, 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के प्रचार का एजेंडा तय कर रहे हैं? गुरुवार को हरिद्वार में बोलेले हुये, भागवत ने कहा था कि 15 वर्ष के अंदर अखण्ड भारत बनाना संभव है तथा हर उस व्यक्ति से निवृत्त लिया जायेगा, जो इस मुहिम की राह में रोड़े अटकयेगा। उन्होंने कहा था, "जहाँ भारत का दर्शन अहिंसा का है, वहीं डंडा लेकर चलना भी जरूरी है," क्योंकि दुनिया ताकत की भाषा ही समझती है। अखण्ड भारत की अवधारणा प्रत्यक्षतः "हिन्दू राष्ट्र" की

अवधारणा से अलग है, क्योंकि आर.एस.एस. के अखण्ड भारत के विचार में मुस्लिम बहुल देश, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान भी शामिल हैं। जैसा कि गुरु गोलवरकर जैसे आर.एस.एस. के सिद्धांतकारों के लेखों एवं ग्रंथों में सामने आया है, अफगानिस्तान या ईरान में रहने वाले लोग भी मूलतः हिन्दू ही हैं, जिन्हें भविष्य में किसी समय "घर वापसी" करने के लिये बाध्य किया ही जायेगा। लेकिन, पिछले 70 सालों में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है तथा ऐसे कई देश, जिन्हें आर.एस.एस. अखण्ड भारत का हिस्सा मानती है, आज परमाणु शक्ति सम्पन्न हैं। भौगोलिक रूप से, भागवत की अखण्ड भारत की अवधारणा

अव्यवहारिक कही जा सकती है क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि चीन, उदाहरणार्थ, भारत को तिब्बत ले लेने देगा। लेकिन अखण्ड भारत का विचार भाजपा के अन्तर्निहित संगठनों तथा उसके समर्थकों-अनुयायियों के लिये भावनात्मक अपील रखता तो प्रतीत होता ही है। आगामी गुजरात तथा अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही, 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिये, भाजपा के लिये यह जरूरी है कि भावात् ब्रिगेड स्वयंसेवकों तथा अन्य सम्बंधित संगठनों की व्यवस्था एवं उत्तेजना यथावत बनाये रखे। खासतौर से इसलिये भी, क्योंकि आर्थिक प्रोथ के मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार कारिकाई बहुत खराब रहा है।

समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने अखण्ड भारत अवधारणा की वकालत की थी तथा भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का एक महासंघ बनाने की चर्चा की थी। लेकिन भागवत की अवधारणा "हिन्दू अखण्ड भारत" की अवधारणा है जिसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। हिन्दी भाषी राज्यों में, भाजपा के टोस जनाधार के बाहर, "हिन्दी को थोपने" के विचार तक का कड़ा विरोध होता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही के उस बयान को, खासतौर से दक्षिणी राज्यों में, विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त विरोध किया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि लोगों को सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिये, अंग्रेजी का नहीं।

ईश्वरप्पा का इस्तीफा

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ईश्वरप्पा पर पुलिस डेकेदार संतोष पाटिल को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का

■ कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना इस्तीफा सौंपा।

मामला दर्ज किया है। इस मामले में राजनीतिक विवाद शुरू होने के बाद ईश्वरप्पा ने गुरुवार शाम मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर एकत्रित हुए ईश्वरप्पा के समर्थकों ने नारेबाजी की।

प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या में वृद्धि

राज्य में शुक्रवार को भी रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 109 हो गए हैं

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 15 अप्रैल। प्रदेश में नए कोरोना संक्रमितों की तुलना में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर फिर सौ के पार हो गए हैं। वहीं इस बीच राज्य में शुक्रवार को 17 नए संक्रमित मिले, जबकि इनकी तुलना में केवल 4 ही रोगी ठीक हुए हैं। हालांकि 31 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण का एक और मामला बढ़ने के साथ 17 नए रोगी मिले हैं। इससे पहले गुरुवार को 16 संक्रमित पाए गए थे। इनमें से 16 राजधानी जयपुर में और एक संक्रमित जोधपुर में मिला है। राजधानी जयपुर में पिछले तीन दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 10 से ऊपर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह है कि शुक्रवार को 31 जिलों अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिराही, टोंक और उदयपुर में कोई भी नया संक्रमित

■ प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 17 नए संक्रमित मिले हैं, जो कि गत दिन के मुकाबले एक ज्यादा है।
■ अकेले जयपुर में 16, जबकि जोधपुर में 1 नया मरीज पाया गया है।
■ हालांकि, राज्य के 31 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है।

नहीं मिला है। इनमें 21 जिले पूरी तरह संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अब यहां न कोई नया संक्रमित है और न ही कोई एक्टिव केस बचा है।
वहीं दूसरी ओर राज्य में शुक्रवार को भी नए संक्रमितों की तुलना में रिकवरी कम हुई है। इस दौरान केवल 4 ही मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बीमारी से 12 लाख 73 हजार 513 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 109 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक 82 मामले जयपुर जिले में हैं।
अन्य जिलों में 10 से कम केस हैं। राज्य में शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमण में रिकवरी कम हुई है। इस दौरान केवल 4 ही मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बीमारी से 12 लाख 73 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

सोनिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सदस्यता अभियान के तहत उसने देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लगभग सभी बूथों पर 2.6 करोड़ सदस्यों को डिजिटल कार्ड अभियान से जोड़ा है। इस डिजिटल सदस्यता के लिए उन्हीं लोगों को पात्र माना गया है जिनकी सदस्यता को किसी अधिकृत सदस्य ने सत्यापित किया है। यह सदस्यता अभियान मोबाइल फोन में कांग्रेस सदस्यता ऐप के जरिए संचालित किया गया। इस ऐप के जरिए नामांकित होने वाले हर व्यक्ति को सारी प्रक्रिया का पालन करने के बाद डिजिटल आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाता है और इसकी प्रामाणिकता क्यूआर कोड से होती है।

रूस का अति शक्तिशाली "वॉर शिप" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितने नौसैनिक इस जहाज के साथ हताहत हुए हैं। यदि जहाज में मौजूद हथियारों की बात की जाए तो इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक थे और शायद किसी मिसाइल के प्रहार ने इसके विस्फोटकों को सुलगा दिया। इससे शायद जहाज पूर्णतया नष्ट हो गया।

नैच्यून वर्ग की मिसाइलों को अब तक पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं माना गया है। तथापि एक विशालकाय जहाज के अचानक ढूँढने से नैच्यून क्लास मिसाइल को प्रभावोत्पत्कता को निश्चित रूप से बढ़ा दिया है। विडम्बना यह है कि मास्कोवा की निर्माण सोवियत संघ के समय में यूक्रेन में ही किया था और 1980 के दशक की शुरुआत में इसका जलावरण किया गया था। यूक्रेन के लोगों ने अपने विजयोउल्लास में कहा है कि जहाज को ढुंढो देना उनके देश के बच्चों और महिलाओं की हत्या करने वाले पुतिन के लिए एक छोटा प्रतिशोध है। ये उम्माव उठाए जा रहे हैं कि जहाज पर एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होने के

बावजूद उस पर यूक्रेन की मिसाइल ने कैसे प्रहार किया। ये मुद्दे युद्ध स्थिति में ऐसे बड़े बड़े युद्धपोत की तैनाती को लेकर सवाल उठाते हैं। अमेरिका ने चीन के तटों पर मौजूद अनेक जहाजों को निर्णायक ढंग से डेटा लिया है क्योंकि वे जहाज चीन के एंटी-शिप मिसाइल बेसेस की फायरिंग रेंज में आ रहे थे। यूक्रेन युद्ध की प्रतिध्वनि पूरे विश्व में पहले ही महसूस की जा रही है। चीन, दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों में अपने नवीनतम लड़ाकू विमान भेज रहा है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस से मिली चुनौती का मुकाबला करने में जब पूरा तरह से व्यस्त है तो ऐसी स्थिति में चीन इस मौके को भुनाकर अपनी ताकत को स्थायित करना चाहता है।

विवाहित से ब्लैकमेल कर बलात्कार का मामला दर्ज

अजमेर, (कासं)। रामगंज थाना क्षेत्र में एक विवाहिता से बलात्कार करने के मामले सामने आया है। पीड़ित विवाहिता ने रामगंज थाने में आरोपी सहित उसका साथ देने वाली मामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने दर्ज मुकदमे में बताया कि आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया, बलात्कार किया और रूप भी मांगे। पुलिस ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जांच दक्षिण पुलिस उपाधीक्षक मुकेश सोनी को सौंपी गई है।

रामगंज थाना पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र चंदबर्दाई नगर जवाहर की नाड़ी निवासी पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि रवि नायक

व रवि पहले से मौजूद था। आरोपी रवि नायक, फुला देवी, ललिता देवी उसे झंसे में लेकर अपने साथ लेकर किसी दोस्त के घर ले गए। दोस्त को कहीं बाहर भेज दिया था। इस पर जब पीड़िता ने मोबाइल से उसकी फोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो आरोपी रवि और उसकी मामियां ने बदले में उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा और जब पीड़िता ने मना किया तो उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बाद में आरोपियों ने इस दौरान उसकी और अश्लील वीडियो भी बना ली। उसे इंटरनेट पर डालने की धमकियां दी। पीड़ित विवाहिता ने बताया कि उसके बाद से ही आरोपी रवि फोटो वीडियो वायरल की धमकियां देकर कई

बार बलात्कार कर चुका है और हजारों रूपए भी ले चुका है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की धमकियां से परेशान होकर वह अपना फोन बंद कर अपने पीहर चली गई लेकिन आरोपी उसे धमकी दे रहा है। इस कारण विवाहिता मानसिक रूप से परेशान है। विवाहिता ने परेशान होकर मामले में रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रामगंज थाना पुलिस ने मामले में दुष्कर्म और रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। मामले की जांच दक्षिण पुलिस उपाधीक्षक मुकेश सोनी कर रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित विवाहिता का जवाहलाल नेहरू अस्पताल से बलात्कार संबंधी मैडिकल भी कराया है।